

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

अवयव

राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम में पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) एक

गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीयों को कवर करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

[६] [Age] 60 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वे IGNOAPS के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। [of]

60-79 आयु वर्ग के सभी IGNOAPS लाभार्थियों को मासिक पेंशन रु। 300 (केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये)।

उन 80 वर्षों और उससे अधिक की मासिक पेंशन राशि 500 रुपये प्राप्त होती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए जोरदार तरीके से आग्रह किया जाता है ताकि लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हो सके। 8]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

वर्ष 2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), रुपये की मासिक पेंशन के साथ 40 से 64 (बाद में संशोधित 40 से 59) आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है। 200 प्रति लाभार्थी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। उन्हें 2000 तक मिलना चाहिए। यह कार्यक्रम 2007 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

पात्रता:

80 वर्ष से अधिक की विकलांगता और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति।

राशि: years 300 (यूएस \$ 4.30) प्रति माह (years 500 (यूएस \$ 7.20) उन 80 वर्षों और उससे अधिक के लिए)।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)

एक घर में रोटी-विजेता की मृत्यु की स्थिति में, शोक संतप्त परिवार को 40,000 की सहायता प्राप्त होगी। ब्रेड-विजेता की उम्र 18-64 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक घर में प्राथमिक रोटी-विजेता की मृत्यु के हर मामले में सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्नपूर्णा योजना

इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, जो हालांकि पात्र हैं, जिन्हें IGNOAPS के तहत खुला रखा गया है। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल प्रदान किया जाता है।

आराम पात्रता मानदंड

कई राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से परे सामाजिक पेंशन का कवरेज बढ़ाने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने या राज्य स्तर की पेंशन योजनाओं को शुरू करने के लिए बीपीएल पद्धति का उपयोग करना बंद कर दिया है।

दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों ने बहिष्करण मानदंडों को अपनाते हुए लगभग सार्वभौमिक कवरेज में स्थानांतरित कर दिया है (उदाहरण के लिए, हरियाणा में 59 वर्ष से अधिक आयु के सभी निवासी, सभी स्रोतों से वार्षिक आय Haryana 2 लाख से कम) (यूएस \$ 2,900) पुराने के लिए पात्र हैं -एज पेंशन) [10]

अन्य राज्यों ने राज्य पेंशन योजनाएं शुरू की हैं जो गैर-बीपीएल परिवारों के व्यक्तियों को कवर करती हैं जो एनएसएपी के तहत सामाजिक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा में 59 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्ग और विधवाएं जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 350 24,000 (US \$ 350) से कम है, मधु बाबू पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। [11]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में केवल 4059 आयु वर्ग की विधवाएँ शामिल हैं, कुछ राज्य सरकारों ने राज्य विधवा पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ में, सुख सहारा योजना 18-50 आयु वर्ग की सभी विधवाओं को एक मासिक पेंशन प्रदान करती है। [12] बिहार में लक्ष्मी बाई पेंशन योजना [13] में 18 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाएँ शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय below 60,000 (US \$ 870) से कम है।

इसी तरह, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) केवल 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को कवर करती है। कवरेज में इस अंतर को संबोधित करने के लिए, बिहार [14] और राजस्थान [15] जैसे राज्यों ने राज्य विकलांगता पेंशन योजनाएं शुरू की हैं जो 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को कवर करती हैं।

पेंशन राशि में वृद्धि

भारत सरकार ने राज्य सरकारों से मासिक पेंशन राशियों को दोगुना करने के उद्देश्य से मिलान योगदान देने का आग्रह किया है। नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में मासिक पेंशन राशि दिखाती है:

पेंशन परिषद

पेंशन परिषद - भारत में सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक पहल - मांग की गई है कि भारत सरकार मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 50% से कम नहीं के साथ "गैर-अंशदायी और सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली स्थापित करे" न्यूनतम वेतन या ₹ 2,000 (यूएस \$ 29), जो भी अधिक हो। "[39]

कोई भी व्यक्ति 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होना चाहिए; महिलाओं के लिए, पात्रता 50 वर्ष या उससे अधिक हो

बहिष्करण के लिए एपीएल / बीपीएल मानदंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

मुद्दे और बहस

लाभार्थियों की पहचान के लिए बीपीएल पद्धति का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए बीपीएल स्थिति का उपयोग करने के लिए भारत में [४०] [४१] [४२] [४३] बहस चल रही है। यह सामाजिक पेंशन के लिए विशेष रूप से सच है जहां कई गरीब बुजुर्ग, विधवा और विकलांगता वाले व्यक्तियों को एनएसएपी से बाहर रखा गया है क्योंकि उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है। [४४] कई राज्यों ने अपनी वार्षिक आय के आधार पर गैर-बीपीएल व्यक्तियों को शामिल करके या सरकारी नौकरियों वाले लोगों को बाहर करने के लिए एक साधारण बहिष्करण मानदंडों का उपयोग करके या भूमि की एक निश्चित राशि से अधिक की राशि के साथ पेंशन योजनाओं के कवरेज का विस्तार किया है।

कम मासिक पेंशन राशि

भारत में बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन में वृद्धि नहीं करने के लिए भारत सरकार की कड़ी आलोचना हुई है। कठोर आलोचना तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से हुई, जिन्होंने कम मासिक पेंशन राशि को बुजुर्गों की गरिमा का

अपमान बताया। [४५] जबकि भारत सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों को सामाजिक पेंशन में एक महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, फिर भी यह राशि पिछले एक दशक में जीवन लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। पेंशन परिषद ने मांग की है कि सरकार मासिक पेंशन को न्यूनतम वेतन के आधे या (2,000 (यूएस \$ 29) तक बढ़ाती है, जो भी अधिक हो।